नंदिग्राम टाईम्स

RNI NO. MAHHIN/2016/69743 EDITOR : SHAIKH JAHUR AHEMAD

Sunday 11th January 2026 | ● वर्ष - 9 | ● अंक 256 | ● पृष्ठ 04 | ● मूल्य - 2 रूपए | ● www.nandigramtimes.com

केंद्र के जाति-आधारित जनगणना निर्णय का स्वागत, तमिलनाडु सीएम स्टालिन और कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर की प्रतिक्रिया

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने आगामी राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना के साथ जाति-आधारित जनगणना कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसे विपक्षी नेताओं ने स्वागतयोग्य बताया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस फैसले को सामाजिक न्याय और सबको बराबरी के अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधियों को मिलाकर एक सलाहकार परिषद बनाई जाए ताकि नीति-निर्माण में विविध दृष्टिकोण शामिल हों और प्रक्रिया संवेदनशीलता से संचालित हो। स्टालिन ने यह भी स्पष्ट किया कि जातिगत जनगणना एक संवेदनशील विषय है और इसे सावधानीपूर्वक लागू किया जाना चाहिए ताकि सामाजिक तनाव न पैदा हो।

कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद मणिकम टैगोर ने भी इस निर्णय का समर्थन किया है और इसे डेटा-आधारित सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि यह कदम उन लंबे समय से उठाई जा रही मांगों को साकार करने में मदद करेगा और नीति बनाने में स्पष्टता लाएगा।

Indian Politics | सुधांशु त्रिवेदी ने ओवैसी को दी सीधी चुनौती

पहले अपनी पार्टी का अध्यक्ष 'हिजाब वाली महिला' को बनाकर दिखाइए, सुधांशु त्रिवेदी ने ओवैसी को दी सीधी चुनौती

नई दिल्ली: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब वाली महिला को एक दिन प्रधानमंत्री बनने संबंधी बयान पर सियासी हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने का सपना फिलहाल सपना ही रहने वाला है। पहले वह अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी हिजाब पहनने वाली महिला को बनाकर दिखाइए। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने ओवैसी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि दुनिया के कई मुस्लिम देशों में महिलाएं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रह चुकी हैं, लेकिन उनमें से कितनी महिलाओं को बुर्का पहने देखा गया है, यह एक बड़ा सवाल है।

सुधांशु त्रिवेदी ने बेगम खालिया जिया और शेख हसीना का दिया उदाहरण

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन वे आमतौर पर बुर्के में नजर नहीं आईं। इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और इंडोनेशिया की पूर्व प्रधानमंत्री मेघावती सुकर्णोपुत्री का भी जिक्र करते हुए कहा कि इन उदाहरणों से ओवैसी के बयान की वास्तविकता पर सवाल खड़े होते हैं।

ओवैसी मुस्लिम परंपरा को लेकर अपना नजरिया स्पष्ट करें

सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि ओवैसी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनका मुस्लिम परंपरा को लेकर जो नजरिया है, वह पैगंबर मोहम्मद के वंश से कैसे मेल खाता है और सऊदी अरब तथा जॉर्डन जैसे देशों के शाही परिवार, जो खुद को उस वंशावली से जोड़ते हैं, उसमें कहां फिट बैठते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि जो काम दुनिया के बड़े-बड़े मुस्लिम देश नहीं कर रहे हैं और जिन देशों में पैगंबर मोहम्मद साहब के वंश से जुड़े शासक हैं, वहां भी इस तरह की परंपराएं नहीं दिखतीं, लेकिन भारत में ओवैसी और इंडी गठबंधन के कई नेता इसी मुद्दे पर सियासत करने में जुटे हुए हैं।

प्रधानमंत्री बनने का सपना फिलहाल सपना ही रहने वाला है: सुधांशु त्रिवेदी

भाजपा सांसद ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने का सपना फिलहाल सपना ही रहने वाला है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि पहले हकीकत में कुछ करके दिखाइए और अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी हिजाब पहनने वाली महिला को बनाकर दिखाइए, तब यह समझ में आएगा कि ओवैसी की बातों में कितनी सच्चाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी की राजनीति में मुस्लिम महिलाओं के प्रति वास्तविक संवेदना कम और राजनीतिक स्वार्थ अधिक नजर आता है।

सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश यादव की एसआईआर वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया

इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश यादव की एसआईआर के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर इंडिया गठबंधन की स्थिति बेहद उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की हालत यह हो गई है कि वे न खुलकर बोल पा रहे हैं और न ही चुप रह पा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव कह रहे थे कि भाजपा के वोट कट रहे हैं, जबकि कांग्रेस यह दावा कर रही थी कि एसआईआर के कारण विपक्ष के वोट कट रहे हैं। अब वही नेता कह रहे हैं कि एसआईआर वोट काटने के लिए नहीं, बल्कि वोट जोड़ने के लिए है।

एनएसए अजीत डोभाल ने कहा- मैं मोबाइल/इंटरनेट का उपयोग नहीं करता, युवाओं को दिया दूरदर्शी संदेश

NEWS AGENCY

नई दिल्ली : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम में एक चौंकाने वाला बयान दिया कि वे मोबाइल फोन और इंटरनेट का नियमित उपयोग नहीं करते। कार्यक्रम में एक युवा ने उनसे पूछा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले व्यक्ति डिजिटल तकनीकों का उपयोग क्यों नहीं करते, तो डोभाल ने स्पष्ट किया कि वे केवल पारिवारिक या निजी बातों के लिए ही कभी-कभार फोन का इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट का उपयोग नहीं करते। उन्होंने बताया कि उनके पास संपर्क करने के अन्य कई साधन हैं, जो आम लोगों को पता नहीं हैं, और काम चल जाता है। उन्होंने कहा कि तकनीक पर निर्भरता कम करने का यह निर्णय आत्म अनुशासन और दूरदर्शिता का हिस्सा है। डोभाल ने युवाओं को निर्णय लेने में आगे सोचने की प्रेरणा दी और कहा कि आज के फैसले भविष्य को आकार देते हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

गाज़ियाबाद में मतदाता सूची के SIR में 1.53 लाख 'अनमैप' वोटरों को नोटिस भेजे जाएंगे

उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के पहले चरण के परिणाम सामने आए हैं। इस प्रक्रिया के तहत सख्ती से वोटरों की सूची का सत्यापन किया गया और पता चला कि जिले में लगभग 1.6 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका डेटा पुराने 2003 के मतदाता रिकॉर्ड से मैप नहीं हो सका। ऐसे मतदाताओं को "अनमैप्ड" श्रेणी में रखा गया है, जिनके विवरण और पहचान अब तक इलेक्ट्रोरल रोल के साथ मेल नहीं खा पा रहे हैं। इन सभी मतदाताओं को सत्यापन के लिए आधिकारिक नोटिस भेजे जाएंगे, ताकि वे आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अपनी पात्रता साबित कर सकें। इसमें पहचान पत्र, निवास प्रमाण जैसे दस्तावेज माँगे जाएंगे। अगर समय पर पुष्टिकरण नहीं हुआ, तो उनके नाम को अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने में कठिनाई आ सकती है।

विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची में अनुपस्थित, स्थानांतरित, दुर्लभ तथा मृत के रूप में दर्ज कई नामों को हटाया गया है। इसी कारण गाज़ियाबाद की पुरानी सूची में करीब 28.37 लाख मतदाताओं में से अब नए मसौदा रोल में लगभग 20.19 लाख मतदाता ही पाए गए हैं। इससे करीब 8.18 लाख नाम हटाए गए हैं, जिनमें से कई अनमैप्ड श्रेणी के हैं।

प्रशासन ने नोटिस की प्रक्रिया के लिए बूथ-स्तर अधिकारियों (BLO) को तैनात किया है, जो मतदाताओं तक दस्तावेज सत्यापन संबंधी नोटिस पहुँचाएंगे। मतदाता सूची को अपडेट, साफ-सुथरा और त्रुटिरहित बनाने के लिए यह कदम आवश्यक बताया जा रहा है, ताकि आगामी चुनावों में किसी भी मतदाता को मतदान प्रक्रिया से वंचित न होना पड़े। प्रक्रिया के बाद दावा-आपत्तियों की सुनवाई अवधि निर्धारित की जाएगी और अंतिम वोटर सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित होने की संभावना है।

सीतामढ़ी में सीएम परिभ्रमण योजना के फंड विवाद के बीच 82 प्रधानाध्यापकों की सैलरी में कटौती की तैयारी

बिहार के सीतामढ़ी जिले में मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना से जुड़े फंड के उपयोग में गंभीर लापरवाही सामने आई है। इस मामले में शिक्षा विभाग ने जिले के 82 सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के वेतन में कटौती करने का निर्णय लिया है। बताया गया है कि इन प्रधानाध्यापकों द्वारा बीते करीब सात वर्षों में योजना के तहत मिले लगभग 16.40 लाख रुपये का समुचित लेखा-जोखा अब तक विभाग को नहीं सौंपा गया है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी के अनुसार, फंड के हिसाब के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए और विशेष शिविर भी लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद केवल छह स्कूलों ने ही संतोषजनक विवरण प्रस्तुत किया। शेष प्रधानाध्यापकों द्वारा लगातार लापरवाही बरते जाने के कारण विभाग को सख्त कदम उठाना पड़ा।

शिक्षा विभाग का कहना है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय के भीतर फंड का पूरा हिसाब नहीं दिया गया, तो आगे और कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस कार्रवाई के बाद जिले के शिक्षा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और कई प्रधानाध्यापक जल्द ही दस्तावेज जमा करने की तैयारी में जुट गए हैं।

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त: किसानों का इंतजार जारी, फरवरी 2026 में मिल सकती है राशि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) की 22वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता है। योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजा जाता है। 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की जा चुकी है। अब 22वीं किस्त जनवरी-मार्च 2026 के बीच, मुख्यतः फरवरी 2026 में जारी होने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है।

किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे e-KYC और Farmer ID जैसी जरूरी प्रक्रिया समय से पूरा कर लें, अन्यथा उनकी राशि रुक सकती है। योजना में बदलाव के तहत अब Farmer ID को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे बिना ID वाले किसानों को 22वीं किस्त नहीं मिल सकती।

किसानों को सलाह है कि वे आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर अपना स्टेटस चेक करें और कोई जरूरी अपडेट रह जाने पर उसे जल्द पूरा करें, ताकि ₹2,000 की आगामी किस्त समय पर उनके खाते में ट्रांसफर हो सके।

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: 7वें वेतन आयोग के तहत DA/DR में 2 फीसदी वृद्धि संभव

NEWS AGENCY

केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अंतर्गत डीअर्नेस अलाउंस (DA) और डीअर्नेस रिलीफ (DR) में लगभग 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के लिए तैयार है, जिससे यह जनवरी 2026 से 58% से बढ़कर लगभग 60% हो सकता है। यह कदम महंगाई के बढ़ते दबाव को कम करने और सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनरों की आय में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। वर्तमान DA वृद्धि 7वें वेतन आयोग के तहत आख़िरी चरण की संभावना है, क्योंकि इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। इस सन्दर्भ में आंकड़े महंगाई के औसत इंडेक्स (AICPI-IW) पर आधारित हैं, जो जनवरी 2026 के लिए DA को 2% बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं।

इस वृद्धि का फायदा केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ लाखों पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। DA दर में 2% की बढ़ोतरी सीधे तौर पर मासिक वेतन और पेंशन में इजाफा करेगी, जिससे महँगाई से निपटने में मदद मिलेगी। हालांकि यह वृद्धि पिछले कई वर्षों की तुलना में कम मानी जा रही है, क्योंकि सामान्यतः DA में 3% या उससे अधिक का इजाफा होता रहा है।

विश्लेषकों के अनुसार, यह 2% वृद्धि 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आख़िरी DA संशोधन के रूप में देखी जा रही है और आगे 8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव लागू होने तक DA में संभावित संशोधन सीमित रह सकता है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को यह वृद्धि वित्तीय राहत दे सकती है और उनकी आर्थिक स्थितियों में स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगी।

उमरखेड नगर पालिका में उपाध्यक्ष पद पर सियासी शह-मात तेज, रसूल पटेल का नाम सबसे आगे, 16 जनवरी को होगा बड़ा फैसला

उमरखेड नगर पालिका में जनशक्ति पैनल की स्पष्ट जीत के बाद अब उपाध्यक्ष पद और तीन स्वीकृत सदस्यों के चयन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 16 जनवरी, शुक्रवार को होने वाली इस अहम बैठक पर पूरे शहर की नजरें टिकी हुई हैं।

नगर पालिका चुनाव में जनशक्ति पैनल के 17 नगरसेवक, जिनमें नगराध्यक्ष भी शामिल हैं, विजयी हुए हैं। यह पैनल कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) और जनशक्ति के संयुक्त सहयोग से बना है। नगराध्यक्ष पद पर तेजश्री जैन के निर्वाचित होने के बाद अब उपाध्यक्ष पद कांग्रेस या 'उबाठा' गुट को मिलने की संभावना जताई जा रही है।

शहर में अब तक चली आ रही परंपरा के अनुसार उपाध्यक्ष पद पर मुस्लिम प्रतिनिधि को अवसर दिए जाने की चर्चा है। यदि यह परंपरा कायम रहती है तो कांग्रेस के रसूल पटेल या जुबेर कुरैशी का नाम आगे आ सकता है। वहीं 'उबाठा' गुट की ओर से स्वाती ठाकरे के नाम पर भी मंथन जारी है।

इसके साथ ही तीन स्वीकृत सदस्यों के चयन को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। जनशक्ति पैनल से दो और भाजपा से एक स्वीकृत सदस्य चुना जाना तय माना जा रहा है। अनुभवी और युवा चेहरों के बीच संतुलन किसे मिलेगा, इसका फैसला 16 जनवरी को ही सामने आएगा।

पेंशन: भरोसा या इंतज़ार? – केंद्र और महाराष्ट्र की नीति की कसौटी

संपादकीय... |

केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियाँ पेंशनभोगियों की सुरक्षा और सम्मान के सवाल पर किस हद तक भरोसेमंद हैं? 10 जनवरी 2026 तक की स्थिति का विश्लेषण।

---संपादकीय...

जब एक सेवा-पूर्ण जीवन के बाद पेंशनभोगी रोज़मर्रा की चुनौतियों से जूझते हैं — महंगाई, स्वास्थ्य खर्च, दवाइयाँ और परिवार की ज़रूरतें — तब पेंशन न केवल आर्थिक लाभ होती है, बल्कि वह सम्मान, सुरक्षा और राज्य का वादा भी होती है। 10 जनवरी 2026 तक केंद्र सरकार और Govt of Maharashtra द्वारा पेंशन से जुड़े फैसले इसी सवाल के इर्द-गिर्द हैं: क्या पेंशन एक अधिकार के रूप में सुरक्षित है या केवल इंतज़ार की सूची में रखा गया है?

सबसे बड़ा केंद्र स्तर का अपडेट यह है कि केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) की कार्यावधि और Terms of Reference को पारित कर दिया है, जिससे अनुमान है कि लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों का वेतन और पेंशन संरचना संशोधित हो सकती है। (Economic Times, 10 Jan 2026)

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है, हालांकि अंतिम मंज़ूरी और वित्तीय प्रावधान बाद में तय होंगे। यह वही आयोग है जो प्रत्येक दशक में अमल में आता है और देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं के अनुरूप वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करता है। 7वें आयोग के बाद 10 वर्षों में महंगाई के कारण पेंशनभोगी और कर्मचारी नई समीक्षा के बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं — जिसमें पेंशन दरों का पुनर्गठन, Fitment Factor और DA/DR (Dearness Allowance/Dearness Relief) का समायोजन शामिल है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन भत्तों में कटौती नहीं होगी और DA/DR के लाभ जारी रहेंगे। PIB Fact Check ने साफ़ किया है कि किसी भी पद पर यह घोषणा नहीं की गई है कि पेंशनभोगियों के DA या वेतन आयोग लाभ को समाप्त कर दिया गया है। (Press Information Bureau, Govt of India, 9 Jan 2026)

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भी कहा है कि आयोग अपनी रिपोर्ट लगभग 12-18 महीनों में प्रस्तुत करेगा, और उसके बाद ही संसाधन आवंटन के अनुसार पेंशन और वेतन में बदलाव का क्रियान्वयन होगा। (Ministry of Finance, Govt of India) इससे स्पष्ट है कि वेतन आयोग का लाभ तत्काल नहीं मिलेगा, बल्कि दीर्घकालिक प्रक्रिया के तहत लागू होगा।

पेंशनभोगियों के नजरिए से DA/DR का स्तर उनकी जीवनशैली को सीधे प्रभावित करता है। राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार DA/DR में अनुमानित सुधार, महंगाई के लिहाज़ से 3-5 प्रतिशत तक की वृद्धि के संकेत दे रहे हैं, जिससे पेंशनभोगियों को कुछ राहत मिल सकती है। (Latestly, 2026)

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो 9 जनवरी 2026 को National Coordination Committee Pensioners' Association (NCCPA) ने पेंशन अधिनियम 2025 में संशोधनों के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने TA (यात्रा भत्ता), DA और अन्य लाभों को कम करने के प्रस्तावों के खिलाफ आवाज़ उठाई। (Times of India, 9 Jan 2026)

Govt of Maharashtra ने राज्य स्तर पर पेंशनधारियों को राहत देते हुए Dearness Relief (DR) को संशोधित किया है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, 1 जनवरी 2025 से DR दर को 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया गया है। (Govt of Maharashtra, Finance Dept, 2025)

महाराष्ट्र के उन पेंशनभोगियों के लिए, जिनकी पेंशन पुराने वेतन आयोगों के अनुसार तय की गई थी, वहां भी DR मान अलग-अलग लागू किए गए हैं, ताकि विविध सेवाकालों के पेंशनभोगियों को समान आधार पर राहत मिले।

केंद्रीय और राज्य स्तरीय पेंशन नीति संशोधनों का मूल संदेश यह है कि सरकारें पेंशनभोगियों की चिंता को मान रही हैं, लेकिन स्पष्ट समय सीमा और संसाधन आवंटन अब भी अधूरे हैं। पेंशनभोगी चाहते हैं कि पेंशन केवल एक लाभ न रहे, बल्कि सम्मानजनक जीवन की गारंटी बने।

10 जनवरी 2026 तक की स्थिति यही है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर प्रक्रियाएँ जारी हैं, लेकिन अंतिम स्पष्टता और क्रियान्वयन अब भी प्रतीक्षित है। पेंशन के भरोसे और सुरक्षा कवच में अभी भी विश्वास जोड़ने की आवश्यकता है — ताकि सेवा-पूर्ण जीवन का फल केवल इंतज़ार की रेखा में न रह जाए, बल्कि हर पेंशनभोगी तक वास्तविक रूप से पहुँच सके।

WORLD NEWS | पाकिस्तान ने अरब सागर में कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया

पाकिस्तान ने अरब सागर में कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया, जानें भारत की कैसे बढ़ेगी टेंशन

इस्लामाबाद: पाकिस्तानी नौसेना ने अरब सागर में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल का नाम LY-80 (N) है। यह एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे खास तौर पर ड्रोन और नीचे उड़ान भरने वाले हवाई ऑब्जेक्ट्स के लिए विकसित किया गया है। यह परीक्षण शनिवार को उत्तरी अरब सागर में किया गया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन (ISPR) के बयान में बताया गया कि उसने वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से LY-80 (N) सरफेस टू एयर मिसाइल (SAM) को लंबी दूरी तक फायर किया, जो "ऑपरेशनल तैयारी और युद्ध की तैयारी" को दिखाता है।

ISPR ने क्या बताया

इसमें कहा गया है, "LY-80 (N) SAM ने सफलतापूर्वक एक हवाई टारगेट को निशाना बनाया और उसे खत्म कर दिया, जो पाकिस्तान नेवी की मजबूत एयर डिफेंस क्षमताओं को दिखाता है।"

बयान में कहा गया है कि इस अभ्यास में लॉइटरिंग म्यूनिशन (LM) का इस्तेमाल करके सतह के टारगेट को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया, जो सटीक हमले की क्षमताओं को दिखाता है। LY-80 (N) मिसाइल ने सफलतापूर्वक सतह के टारगेट को निशाना बनाया और नष्ट कर दिया, जो "आधुनिक नौसैनिक युद्ध में इसकी प्रभावशीलता" को दिखाता है।

पाकिस्तान ने USV का भी टेस्ट किया

पाकिस्तान ने इसके अलावा मानव रहित सतह पोत (USV) का खुले समुद्र में सफल परीक्षण किया। आईएसपीआर ने अपने बयान में इसे ऑटोनॉमस नौसैनिक टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण छलांग बताया है।

बयान में कहा गया है कि परीक्षणों ने हाई-स्पीड परफॉर्मेंस को मिशन-क्रिटिकल ड्यूरेबिलिटी के साथ जोड़ने की प्लेटफॉर्म की क्षमता को भी देखा गया। इसमें कहा गया है, "दिखाई गई मुख्य क्षमताओं में अत्यधिक गतिशीलता, सटीक नेविगेशन और मौसम प्रतिरोध शामिल हैं। USV एक टैक्टिकल इंटरसेप्टर की स्टील्थ के साथ कम जोखिम वाला, उच्च प्रभाव वाला समाधान प्रदान करता है।"

भारत की कैसे बढ़ेगी टेंशन

पाकिस्तान की भारत से कट्टर दुश्मनी है। पिछले साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक संघर्ष हुआ था, जिसमें बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया है, वह स्वार्म ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन को निशाना बनाने में सक्षम है। ऐसे में अगर भविष्य में कभी युद्ध होता है तो पाकिस्तान इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय हमलों को विफल करने के लिए कर सकता है।

WORLD NEWS | वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने ये कैसी रैंकिंग जारी की

दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत नहीं, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने ये कैसी रैंकिंग जारी की

NEWS AGENCY

वॉशिंगटन: वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने 2026 के दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी की है। इस सूची में हर बार की तरह अमेरिका शीर्ष पर है। दूसरा स्थान रूस को और तीसरा चीन के पास है। वहीं, इस बार शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत शामिल नहीं है। भारत को 12वें स्थान पर रखा गया है। जबकि, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है।

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने क्या कहा

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू का दावा है कि उसने यह रैंकिंग आर्थिक क्षमता, सैन्य संसाधन, तकनीकी प्रगति, जनसांख्यिकीय शक्ति, शासन स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में प्रभावी ढंग से भाग लेने की क्षमता के संयोजन से निर्धारित की है।

इसमें शामिल देशों को सैन्य गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और नेतृत्व जैसी पांच विशेषताओं पर परखा जाता है। जो देश उच्च रैंक पर होते हैं, वे इन सभी क्षेत्रों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिससे विश्व मंच पर उनका पहचान और प्रभाव बढ़ता है।

दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को चुनना मुश्किल

रिपोर्ट में आगे कहा गया, "दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को परिभाषित करना जितना सोचा जाता है, उससे कहीं ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। शक्ति कई रूपों में होती है, सैन्य शक्ति से लेकर आर्थिक ताकत, राजनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव तक। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश वैश्विक आर्थिक पैटर्न को आकार देते हैं, एक मजबूत सेना बनाए रखते हैं और ऐसी विदेश नीतियां बनाते हैं जिनके प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस होते हैं।"

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने ये कैसी रैंकिंग जारी की

सर्वे के आधार पर जारी होती हैं रैंकिंग

इसमें बताया गया है, U.S. News and World Report, BAV Group और पेन्सिलवेनिया यूनिवर्सिटी के व्हार्टन स्कूल के साथ मिलकर, अपनी सालाना बेस्ट कंट्रीज़ रैंकिंग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की रैंकिंग जारी करता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस रैंकिंग को जारी करने के लिए दुनियाभर में सर्वे किया जाता है। इन सर्वे में कुछ निश्चित बिंदुओं पर लोगों से प्रतिक्रियाएं मांगी जाती है।

दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देश

क्रम संख्या	देश
1	अमेरिका
2	चीन
3	रूस
4	यूनाइटेड किंगडम
5	जर्मनी
6	दक्षिण कोरिया
7	फ्रांस
8	जापान
9	सऊदी अरब
10	इजरायल

WORLD NEWS | मोदी से तकरार और मुनीर से प्यार...

मोदी से तकरार और मुनीर से प्यार... पेशावर में युद्धाभ्यास कर रहे अमेरिका और पाकिस्तान, भारत की बढ़ेगी टेंशन

इस्लामाबाद: भारत के साथ टैरिफ को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी पाकिस्तान पहुची है। इस टुकड़ी में शामिल अमेरिकी सैनिकों को पेशावर के पास पब्बी लेकर जाया गया है। पब्बी खैबर पख्तूनख्वा सूबे की एक तहसील है, जो पेशावर के नजदीक है। यह जगह अफगानिस्तान की सीमा से भी नजदीक है। अफगान तालिबान भी लगातार सवाल उठा रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की इजाजत दी है, ताकि वह अफगानिस्तान पर नजर रख सके। पाकिस्तानी सेना के प्रॉपगैंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने बताया है कि अमेरिकी सैनिक युद्धाभ्यास के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं।

पाकिस्तानी सेना ने क्या बताया

आईएसपीआर ने बताया है कि अमेरिकी सैनिक युद्धाभ्यास के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं।

इस युद्धाभ्यास का नाम इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 है। इसका आयोजन पाकिस्तान और अमेरिका के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने और आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञता साझा करने के लिए किया गया है। पब्बी में आयोजित यह युद्धाभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 का 13वां संस्करण है। ISPR के अनुसार, दो हफ्ते तक चलने वाले इस अभ्यास में पाकिस्तानी और अमेरिकी सेनाओं के दल शामिल हैं। दोनों पक्षों के अधिकारियों ने उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान के पब्बी में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में उद्घाटन समारोह में भाग लिया। पाकिस्तान-अमेरिका युद्धाभ्यास का मकसद क्या है

बयान में बताया गया है कि अमेरिका-पाकिस्तान युद्धाभ्यास का मकसद आतंकवाद विरोधी अनुभवों को साझा करके आपसी समझ और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है।

इसके साथ ही प्रभावी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए जरूरी रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाना है। ISPR ने एक बयान में कहा, "शहरी युद्ध के दौरान निशानेबाजी कौशल पर, साथ ही एक-दूसरे के ऑपरेशनल सिद्धांतों और सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने पर जोर दिया जा रहा है।"

पाकिस्तान-अमेरिका संबंध हुए मजबूत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध मजबूत हुए हैं। दोनों देशों में सुरक्षा सहयोग पहले से ही जारी था। अब आर्थिक जुड़ाव को भी मजबूत किया जा रहा है। कई अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में तेल की खोज और उत्पादन में शामिल होना चाहती हैं। इसके अलावा क्रिप्टो के लेकर भी पाकिस्तान अमेरिका सहयोग कर रहे हैं। अफगानिस्तान के ताजा हालात के कारण भी ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो दे रहा है, ताकि इलाके में अपनी मौजूदगी को बनाए रख सके।

महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ

नंदिग्राम टाईम्स

Sunday 11th, January 2026 वर्ष - 9 , अंक 256 , पृष्ठ 03

एक दिन हिजाब वाली महिला बनेगी भारत की PM, ओवैसी के इस बयान पर नितेश राणे का पलटवार, बोले- नो चांस

सोलापुर: महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत और पाकिस्तान के संविधानों की तुलना करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे पद केवल एक विशेष धर्म के लोगों के लिए सीमित हैं, जबकि भारत का संविधान हर नागरिक को समान अवसर देता है। ओवैसी ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान की सबसे बड़ी ताकत उसकी समावेशी सोच है। उनके मुताबिक, भारत में कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म या पहनावे से जुड़ा हो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या मेयर बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अंबेडकर का सपना था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भी देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे और भविष्य में ऐसा दिन जरूर आएगा।

राणे ने किया पलटवार

ओवैसी के इस बयान पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू बहुल देश है और यहां इस तरह के बयान स्वीकार्य नहीं हैं। नितेश राणे ने यह भी कहा कि जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, उन्हें अन्य इस्लामिक देशों में जाना चाहिए। उनके बयान ने राजनीतिक हलकों में विवाद को और तेज कर दिया। इस पूरे विवाद पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान भी सामने आए। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, न कि किसी एक व्यक्ति या विचारधारा से।

नेताओं ने दी प्रतिकियाएं

वारिस पठान ने कहा कि संविधान के अनुसार कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मेयर बन सकता है और ओवैसी के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि धमकियों से वे डरने वाले नहीं हैं। उधर, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ओवैसी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर चुनौती दी। उन्होंने कहा कि संविधान किसी को नहीं रोकता, लेकिन ओवैसी को पहले अपनी पार्टी में ही पसमांदा या हिजाब पहनने वाली महिला को शीर्ष पद पर बैठाकर दिखाना चाहिए।

BMC Election: बेटे-बेटी-रिश्तेदार को नगरसेवक बनाने में सांसद-विधायकों ने लगाया एड़ी चोटी का जोर

मुंबई | मुंबई के तीन सांसद और कई सारे विधायक अपने बेटे-बेटी और रिश्तेदारों को जिताने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। यह उनके नाक की बात गई है। बस कुछ भूलकर सिर्फ अपने घर के सदस्य को चुनाव जिताने के लिए रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो सांसद और विधायकों पर उंगली उठाई जाएगी।

तीन सांसदों की बेटी का संघर्ष

उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा से शिंदे सेना के सांसद रविंद्र वायकर की बेटी दीप्ति वायकर-पोतनीस प्रभाग नंबर 173 से उम्मीदवार है। उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा से उद्धव सेना के सांसद संजय दीना पाटील की बेटी राजुला को हरियाली विलेज गोदरेज कॉलोनी प्रभाग नंबर 114 से चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा कांग्रेस से राज्यसभा के सदस्य चंद्रकांत हंडोरे ने अपनी बेटी प्रज्योति को प्रभाग नंबर 140 से उम्मीदवारी दिलाई है। हंडोरे नगरसेवक भी थे और मेयर के रूप में उन्होंने काम भी किया है, वहीं वायकर भी लंबे समय तक नगरसेवक थे। बीएमसी की सबसे मालामाल स्टैंडिंग कमेटी के चार टर्म के नगरसेवक थी थे।

जीत की जोड़ तोड़ में विधायक

बीजेपी सहित तमाम सभी राजनीतिक दलों के विधायक अपने परिवार के सदस्यों की जीत सुनिश्चित करने के लिए तरह-तरह के जोड़ तोड़ कर रहे हैं। विधान परिषद में बीजेपी के सदस्य प्रवीण दरेकर अपने भाई प्रकाश दरेकर की जीत की नैया पार लगाने के लिए प्रभाग नंबर 3 रात दिन एक कर दिए हैं। दिंडोसी से उद्धव सेना के विधायक सुनील प्रभू अपने बेटे अंकित की जीत के लिए प्रभाग नंबर 54 तक सीमित होकर रह गए हैं।

वर्सोवा से ही उद्धव सेना के विधायक हारून खान अपनी बेटी सबा खान की जीत तय करने के लिए प्रभाग 64 के मतदाताओं को मना रहे हैं। चांदिवली विधानसभा से शिंदे सेना के विधायक दिलीप लांडे अपनी पत्नी शैला लांडे (प्रभाग 163) को चुनाव जिताने में लगे हैं। वे पहले भी नगरसेवक का चुनाव जीत चुकी है। भायखला विधानसभा के विधायक मनोज जामसुतकर अपनी पत्नी सोनम (प्रभाग 210) की जीत की डगर साफ करने में लगे हैं। नार्वेकर, नवाब मलिक और असलम की प्रतिष्ठा दाव पर कोलाबा के विधायक व विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मालाड मालवणी से कांग्रेस के विधायक असलम शेख और अजित पवार की पार्टी के नवाब मलिक की प्रतिष्ठा दाव पर है। परिवार के तीन-तीन सदस्यों का टिकट दिया है। राहुल नार्वेकर के भाई की पत्नी यानी भाभी हार्षिता नार्वेकर (प्रभाग 225), भाई मकरंद नार्वेकर (प्रभाग 226) और चचेरी बहन डॉ. गौरवी शिवलकर नार्वेकर (प्रभाग 227) से जिताने के लिए नार्वेकर ने पूरी ताकत झोंक दी है।

मालाड-मालवणी की राजनीति में परिवारवाद एक बार फिर चर्चा में है। कांग्रेस विधायक असलम शेख अपने बेटे हैदर अली (प्रभाग 34), बहन कमरजहां सिद्दीकी (प्रभाग 33) और दामाद सैफ अहद खान (प्रभाग 62) की जीत की रणनीति बना रहे हैं। वहीं अजित पवार की पार्टी ने नवाब मलिक परिवार को तीन टिकट दिए हैं। मलिक की बेटी सना विधायक हैं, जबकि भाई कप्तान मलिक (प्रभाग 165), बहन सईदा (168) और बहू बुसरा नदीम मलिक (170) चुनावी मैदान में हैं। यदि सभी जीते, तो महानगरपालिका में एक ही परिवार के कई सदस्य नजर आएंगे।

नाशिक में भाजपा ने मतदाताओं से 'कमल' पर वोट न देने की अपील की

संवाददाता |

नाशिक: महापालिका चुनाव के बीच नाशिक में भाजपा को अंदरूनी विवाद और एबी फॉर्म (AB Form) गड़बड़ी के कारण अनोखी राजनीतिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने शहर के मतदाताओं से कमल (भाजपा का चुनाव चिन्ह) पर वोट न देने की अपील की है, क्योंकि कुछ प्रभागों में अधिकृत भाजपा उम्मीदवार के बजाय पार्टी के पूर्व नगरसेविका अलका अहिरे को कमल चिन्ह मिल गया है और वे चुनावी मैदान में हैं। इससे पार्टी की रणनीति और मत विभाजन प्रभावित हो रहा है।

भाजपा ने बताया कि एबी फॉर्म के बंटवारे में गड़बड़ी और अनुशासनहीनता के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। अलका अहिरे और पार्टी पदाधिकारी कैलास अहिरे को पार्टी ने हटाकर छह वर्ष के लिए निलंबित किया है, लेकिन उनके पास कमल चिन्ह होने के कारण पार्टी को मतदाताओं से वोट ना देने का अनूठा आह्वान करना पड़ा।

भाजपा नाशिक अध्यक्ष सुनील केदार ने स्पष्ट किया है कि मतदाता पक्ष द्वारा समर्थित अधिकृत उम्मीदवार को ही वोट दें, न कि उस नेता को जिसे पार्टी ने अनुशासनहीनता के कारण बाहर किया है। इस असमंजस की स्थिति एबी फॉर्म विवाद ने उत्पन्न की है, जिससे भाजपा की छवि और चुनावी रणनीति दोनों पर असर पड़ा है। विश्लेषकों के अनुसार, यह मामला पार्टी के आंतरिक संघर्ष और संगठनात्मक चुनौतियों को उजागर करता है, जो चुनाव के अंतिम चरण में लगातार सुर्खियों में रहा है।

ठाणे महापालिका चुनाव: कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, भाजपा-शिंदे गठबंधन पर तीखे आरोप

ठाणे: आगामी ठाणे महानगरपालिका चुनाव 2026 को देखते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने शनिवार को पार्टी का घोषणापत्र (मैनिफेस्टो) जारी किया और भाजपा-शिंदे नेतृत्व पर जमकर हमला बोला। सपकाळ ने आरोप लगाया कि देश में महिलाओं की सुरक्षा बिगड़ती जा रही है और इसके लिए भाजपा ही जिम्मेदार है, क्योंकि कई स्थानों पर बलात्कार के आरोपियों को पार्टी ने टिकट दिया है और ऐसे नेताओं का समर्थन किया जा रहा है, इसलिए आज लोग भाजपा को "बलात्कार जनता पक्ष" कहने लगे हैं।

सपकाळ ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी भ्रष्टाचार और अनैतिक धन कमाई के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समृद्धि महामार्ग जैसी परियोजनाओं में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप हैं और भूमाफियाओं के सहयोग से सरकारी जमीनों को बेचकर धन अर्जित किया जा रहा है।

घोषणापत्र में कांग्रेस ने नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं पर जोर देते हुए कई स्थानीय वादे शामिल किए हैं। पार्टी ने सड़कों को गड्ढा-मुक्त, डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम, महिलाओं के लिए समर्पित बस सेवा, तथा कचरा प्रबंधन लागू करने वाली सोसायटीज़ को संपत्ति कर में छूट देने का वादा किया है। इसके अलावा, झीलों का पुनर्जीवन और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए कई प्रस्ताव भी दिए गए हैं।

सपकाळ ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस भाजपा और शिवसेना-शिंदे नेतृत्व को कभी समर्थन नहीं देगी और विचारों और मूल्यों को सत्ता से ऊपर रखकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने मतदाताओं से स्थानीय प्रशासन में भ्रष्टाचार-मुक्त और सुरक्षित ठाणे बनाने के लिए कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की है।

इस तरह, ठाणे में चुनावी प्रचार और आरोप-प्रत्यारोप के बीच राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है, और मतदाताओं के निर्णय पर आगामी दिनों में चर्चा और दबाव बना रहेगा।

सातारा में नकली खते-कीटनाशक कारखाना ध्वस्त, करोड़ों की सामग्री जब्त

सातारा जिले के वडूज क्षेत्र में कृषि विभाग और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में एक नकली खते और कीटनाशक बनाने वाला कारखाना पकड़ा गया। इस छापेमारी में लगभग 30 लाख रुपये मूल्य की नकली सामग्री जब्त की गई। कार्रवाई में आरोपी प्रतिक काळे को हिरासत में लिया गया है और उस पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

जांच में सामने आया है कि प्रतिक काळे यह नकली रसायन राज्यभर के किसानों और विक्रेताओं को सप्लाई करता था। कृषि विभाग को इसकी सूचना मिली थी, लेकिन आरोपी अपनी गोदाम की जगह बदलते रहने के कारण पकड़ से बच रहा था। अंततः एक विक्रेता के दुकान पर छापेमारी के दौरान इस कारखाने से बनी नकली सामग्री पकड़ी गई और आरोपी तक पहुंच बनाई गई।

जप्त सामग्री में नकली पॅकेजिंग, कच्चा माल और तैयार उत्पाद शामिल थे। जिला कृषि अधिकारी भाग्यश्री पवार ने बताया कि किसानों को किसी भी संदिग्ध खत या कीटनाशक का उपयोग नहीं करने और तुरंत विभाग को सूचना देने की सलाह दी गई है। कार्रवाई के बाद आगे की जांच जारी है।

परभणी-जिंतूर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, कीर्तन से लौट रहे तीन वारकरी की मौत

परभणी-जिंतूर सड़क मार्ग पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में कीर्तन से लौट रहे तीन वारकरियों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब तीनों वारकरी दोपहिया वाहन से घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रही कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि तीनों को गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच शुरू कर दी है। इलाके में शोक का माहौल है।

Maharashtra Politics | उद्धव ठाकरे का अमित शाह को खुला चुनौती

उद्धव ठाकरे का अमित शाह को खुला चुनौती— बोले, अगर हिम्मत है तो अहमदाबाद का नाम 'कर्णावती' रखकर दिखाएं

मुंबई: शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने छत्रपती संभाजीनगर में आयोजित एक चुनावी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खुला चुनौती दी और कहा कि अगर भाजपा के पास हिम्मत है तो आधिकारिक तौर पर अहमदाबाद का नाम बदलकर 'कर्णावती' रख दिया जाए। यह बयान आगामी राजनीतिक संघर्ष में नया मोड़ जोड़ता है, जहां मध्य प्रदेश, गुजरात समेत राष्ट्रीय स्तर पर नाम बदलने के मुद्दे पर बहस तेज हुई है।

ठाकरे ने सभा में कहा कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भाजपा के शासन में शहरों के नाम बदलने के फैसले आए हैं, लेकिन अहमदाबाद जैसे बड़े शहर का नाम बदले जाने पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि मोदी सरकार अहमदाबाद का नाम कर्णावती क्यों नहीं रख रही है, जबकि अन्य कई स्थानों के नाम बदल दिए गए हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, नाम परिवर्तन का मामला संवेदनशील और राजनीतिक रूप से गरम विषय बन चुका है, जहां इतिहास, सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर बहस हो रही है। अहमदाबाद नाम परिवर्तन के लिए सैद्धांतिक आधार भी पहले से चर्चा में रहा है, जिसमें कुछ समूहों ने शहर को प्राचीन नाम "कर्णावती" से जोड़ा है, लेकिन केंद्र या राज्य सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है।

ठाकरे ने सभा में भाजपा पर राजनीतिक दमन और संगठन की कमजोरी का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा केन्द्र तथा राज्य स्तर पर केवल राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों का उपयोग कर रही है, जबकि जनता की समस्याओं पर समाधान नहीं दे रही।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक उद्धव ठाकरे का यह बयान आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद भाजपा के खिलाफ जनता में संवेदीकरण पैदा करना और संस्कृति-नामकरण के विवाद को प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाना है।

वसमत में दिनदहाड़े 'सिने-स्टाइल' लूट: बैंक कर्मचारी की बाइक को टक्कर देकर ₹10 लाख की बुरी चोरी

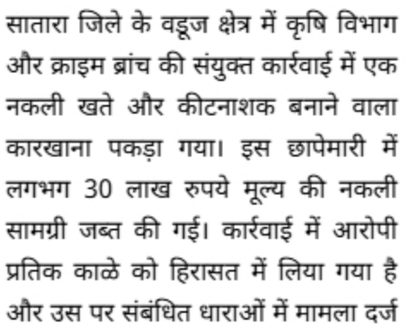

हिंगोली (वसमत): वसमत-कोर्टापाटी मुख्य मार्ग पर शुक्रवार सुबह लगभग 10:45 बजे एक धाड़सी लूट की वारदात सामने आई, जिसमें जिल्हा मध्यवर्ती बैंक का कर्मचारी ₹10 लाख की नकदी लेकर बाइक पर जा रहा था, तभी पीछे से आए अपराधियों ने उसकी बाइक को जोरदार धक्का मारा और रकम भरी बैग छीनकर फरार हो गए।

घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों और नागरिकों ने बदमाशों का पीछा किया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही पुयणी गांव के पास ग्रामीणों ने दो संदिग्धों को दबोच लिया और उन्हें कुरुंदा पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि अपराधी मौके से भागते समय स्पोर्ट बाइक पर सवार थे।

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस घटना ने इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, खासकर जब दिन के उजाले में मुख्य मार्ग पर इस प्रकार की 'सिने-स्टाइल' लूट हुई। नागरिकों का आरोप है कि घटना की सूचना मिलने के बावजूद पुलिस को समय पर अफ़रातफ़री वाले स्थान पर नहीं पहुंचते देखा गया, जिससे कुछ देर रह गई।

पुलिस अब पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या उनके पास इस मामले में और अन्य साथी हैं। साथ ही, चोरी हुई नकदी और घटना के पीछे की साजिश का भी खुलासा किया जाएगा।

यह लूट न केवल बैंक कर्मियों के लिए जोखिम बढ़ाती है, बल्कि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग को भी तेज करती है, ताकि भविष्य में इसी प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके।

नांदेड़ वॉक्स

नांदेड़ जिला > नांदेड़ शहर

नंदिग्राम टाईम्स

Sunday 11th, January 2026 वर्ष - 9 , अंक 256 , पृष्ठ 04

नांदेड महापालिका निवडणूक: २४० महिला रणरागिणी मैदानात, पतियों का प्रचार जोश

नांदेड: आगामी महानगरपालिका चुनाव २०२६ में नांदेड के २० प्रभागों में व्यापक महिला भागीदारी देखी जा रही है, जहां कुल २४० महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। महापालिका में महिलाओं के लिए ५०% आरक्षण के कारण हर प्रभाग में महिलाएं प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं।

अनेक उम्मीदवारों ने पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए राजनीतिक रिंगण में कदम रखा है। कई स्थानों पर अपने पति की सक्रिय मदद से महिलाएं प्रचार-प्रसार में जुटी हैं, जिससे पतियों का प्रचार जोश भी बढ़ा है। उम्मीदवारों का मानना है कि स्थानीय मतदाताओं से सीधे संवाद कर वे अपनी मजबूती साबित कर सकती हैं।

कुछ अनुभवी राजनेताओं को प्रभाग आरक्षण मिल न पाने के कारण सीधे चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नियों को मैदान में उतार कर राजनीतिक संघर्ष जारी रखा है। ऐसा ही देखा गया है कि कई महिलाएं पहली बार अपक्ष या अन्य पार्टियों के टिकट पर चुनावी मुकाबले का हिस्सा बनी हैं। महिला उम्मीदवार घर-घर जाकर मतदाताओं से आशीर्वाद मांग रही हैं और अक्सर खुद को “आपकी लाडकी बहन” बताते हुए समर्थन की अपील कर रही हैं। इससे न केवल प्रचार का तरीका बदल रहा है, बल्कि चुनावी रणनीतियों में भी महिलाओं की बढ़ती सक्रियता साफ दिख रही है।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन २४० महिलाओं में से कितनी महानगरपालिका सभागृह तक पहुंचने में सफल होती हैं और स्थानीय प्रशासन में उनका योगदान कैसा रहता है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऐतिहासिक नांदेड के आधुनिक और समग्र विकास का बड़ा आश्वासन

नांदेड: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नांदेड शहर के व्यापक और आधुनिक विकास के लिए बड़ा दावा किया है। लोकमत से बातचीत में उन्होंने कहा कि नांदेड न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है तथा इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का सरकार दृढ़तापूर्वक प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का नांदेड से गहरा आत्मिक और ऐतिहासिक नाता है। हजूर साहिब गुरुद्वारा की वजह से यह शहर सिख धर्मावलंबियों के श्रद्धास्थल के रूप में विश्वभर में प्रसिद्ध है। इसके चलते नांदेड को और अधिक विकसित एवं सुगम बनाने की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है।

उनकी योजना के अनुसार आधुनिकीकरण और अवसंरचना विकास के कई प्रमुख पहलुओं पर विशेष बल दिया जाएगा। इसमें नांदेड-जालना एक्सप्रेसवे जैसे बड़े मार्ग परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि शहर और आसपास के क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे, सड़क एवं हवाई मार्गों को और अधिक आधुनिक बनाने पर काम तेजी से चल रहा है।

मुख्य मुद्दों में से एक पानी की समस्या को स्थायी रूप से हल करना भी है। अमृत योजना के तहत नांदेड का पानी वितरण नेटवर्क अंतिम चरण में है और इससे दीर्घकालिक तथा संतुलित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, सांडपाणी और मल निस्सारण परियोजनाओं को गती देने के लिए भी विशेष कदम उठाए गए हैं।

नगरपालिका द्वारा घनकचरा प्रबंधन के लिए अलग से आधुनिक प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं, जिनमें बायोगैस और बायोमाइनिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। यह न केवल स्वच्छता बढ़ाएगा बल्कि ऊर्जा के उपायों को भी पर्यावरण हितैषी रूप देगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि नांदेड महानगरपालिका ने राष्ट्रीय स्तर पर पेयजल सर्वेक्षण में पुरस्कार हासिल किया है, जो स्थानीय प्रशासन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सड़कों के विस्तार और मरम्मत के लिए भी करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं जिससे शहर के ट्रैफिक और यातायात सुविधाएँ बेहतर होंगी।

भविष्य की योजनाओं में शहर के आस-पास नए गांवों का नियोजित विकास, शैक्षणिक संस्थानों का आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, तथा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नंदगिरी किले के पुनर्विकास जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। साथ ही, सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए सौर उर्जा योजनाओं को मंजूरी दी जा रही है ताकि महापालिका की ऊर्जा लागत में कमी आए और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले।

इस समग्र दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री फडणवीस ने नांदेड के नागरिकों के लिए एक विकसित, आधुनिक और जीवंत शहर का वादा किया है, जो अपने ऐतिहासिक गौरव को बनाए रखते हुए भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार होगा।

नांदेड में पिपल्स कॉलेज में बालविवाह रोकथाम पर छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम

(स्रोत -जिमाका,नांदेड़)

नांदेड, 10 जनवरी: जिलाधिकारी कार्यालय और बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, नांदेड के संयुक्त प्रयास तथा जिलाधिकारी श्री राहुल कर्डिले के मार्गदर्शन में बालविवाह प्रतिबंध कानून, 2006 के प्रति व्यापक जनजागरूकता अभियान जारी है।

इस अंतर्गत पिपल्स हाईस्कूल, नांदेड में आयोजित कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी कैलास तिडके ने लगभग 500 छात्रों को बालविवाह कानून के महत्व और इसके प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की या 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का विवाह करता पाया जाता है, तो इसके लिए संबंधित परिवारों, विवाह आयोजकों और उसमें शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

तिडके ने स्पष्ट किया कि दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने छात्रों को बालविवाह की सूचना मिलने पर टोल फ्री नंबर 1098 पर तुरंत संपर्क करने का भी आह्वान किया, साथ ही संपर्ककर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

कार्यक्रम का आयोजन पिपल्स हाईस्कूल की ओर से किया गया, जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य सेलमोकर, शिक्षक एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे और कार्यक्रम सफल बनाने में योगदान दिया।

देगलूर न्यायालय का नया अधिष्ठान: आधुनिक इमारत से न्याय की नई छवि

देगलूर, 10 जनवरी 2026 (स्रोत -जिमाका,नांदेड़) : देगलूर शहर के न्यायइतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ा। दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) और न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग की नई न्यायालयीन इमारत का उद्घाटन अत्यंत शिस्तबद्ध और सन्मानपूर्वक माहौल में संपन्न हुआ।

मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीपकुमार सी. मोरे ने भव्य इमारत का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुनील जी. वेदपाठक रहे, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नीरज पी. धोटे प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

1920 से न्यायदान की गौरवशाली परंपरा निभा रही पुरानी न्यायालयीन इमारत की जगह अब आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित नई इमारत तैयार हुई है। इस नई न्यायालयीन इमारत में प्रशस्त न्यायालय कक्ष, स्वतंत्र और सुव्यवस्थित बार असोसिएशन, तथा नागरिकों की सुविधा के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं।

इस ऐतिहासिक समारोह का आयोजन दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) राघवेंद्र नरहरराव देव और देगलूर अभिवक्ता संघ के अध्यक्ष एड. विरेंद्र नागनाथ पाटील ने विशेष परिश्रम से किया। कार्यक्रम का सूत्रसंचालन नांदेड के दिवाणी न्यायाधीश इंदूरकर ने किया।

उद्घाटन समारोह में नांदेड, बिलोली और देगलूर के विधिज्ञ, नागरिक, उपविभागीय पुलिस अधिकारी संकेत गोसावी, पुलिस निरीक्षक मारुती मुंडे, सामाजिक कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नगरसेवक उपस्थित रहे। उपस्थित जनों की उत्स्फूर्त भागीदारी ने नई इमारत के सामाजिक और न्यायिक महत्व को स्पष्ट किया।

समारोह में मान्यवरों ने कहा कि न्यायालय केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि न्याय, संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों की सजीव छवि है। देगलूर में स्थापित यह नई न्यायालयीन इमारत आने वाले दशकों तक न्याय के प्रकाश का दीपस्तंभ बनी रहेगी।

नांदेड महापालिका चुनाव: पूर्व महापौर फिर से मैदान में — हाई-वोल्टेज टक्कर की उम्मीद

नांदेड: नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका निवडणूक प्रचार के अंतिम चरण में प्रवेश करते ही राजनीतिक तापमान बढ़ गया है, जहाँ पूर्व महापौरों ने पुनः चुनावी लड़ाई में वापसी की है और कुछ प्रमुख प्रभागों में ‘हाई-वोल्टेज’ मुकाबले की आशंका जताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, सत्ताधारी दलों ने ८१ में से सभी प्रभागों में उम्मीदवार दिए हैं, जिससे मुकाबला काफी जटिल होता दिख रहा है। कई जगह तीन-तरफा तथा चार-तरफा मुकाबले की स्थिति है, जहां विभिन्न दलों के साथ अपक्ष उम्मीदवार भी हैं, और जाति-धर्म आधारित मत विभाजन परिणाम पर अहम प्रभाव डाल सकता है।

प्रभाग ४ में भाजपा के समर्थन से पूर्व महापौर शैलजा स्वामी और कांग्रेस तथा शिंदेसेना के उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर है। वहीं भाग्यनगर (प्रभाग ५) में पहले महापौर जयश्री पावडे के खिलाफ कई बड़े विरोधी मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी तथा शिंदेसेना के चेहरे शामिल हैं। प्रभाग ६ में कुल आठ उम्मीदवारों की भिड़ंत है, जबकि प्रभाग ९ में पूर्व महापौर बलवंतसिंघ गाडीवाले को चुनौती दी जा रही है। शिवाजीनगर (प्रभाग ८) में भाजपा और शिंदेसेना आमने-सामने हैं, और प्रभाग १८ में एक पूर्व महापौर की बेटी भी चुनावी रिंगण में है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, पूर्व महापौरों की भागीदारी और स्थानीय समीकरण, साथ ही अपक्ष उम्मीदवारों की भूमिका विजय का गणित तय करने में निर्णायक साबित हो सकती है। मतदान के नतीजे, इन हाई-वोल्टेज मुकाबलों के अंतर्गत किस दिशा में जाएंगे, यह आगामी दिनों में स्पष्ट होगा।

चुनाव से पहले परभणी में 50 गांवों में बंटवारे का दावा, सांसद संजय जाधव के बयान से मचा हड़कंप

परभणी जिले में आगामी चुनावों से पहले सियासी माहौल गर्म हो गया है। सांसद संजय जाधव ने दावा किया है कि जिले के करीब 50 गांव राजनीतिक कारणों से आपस में बंट चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ गांवों में दबाव की राजनीति और आपसी तनाव का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। सांसद के इस बयान से प्रशासन और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। उन्होंने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशासन से सतर्कता बढ़ाने और तत्काल कदम उठाने की मांग की है।

नांदेड़ में अशोकराव चव्हाण ने कांग्रेस पर लगाया ‘संविधान बदलने’ का प्रचार का आरोप, जनता को पाठ पढ़ाने का आह्वान

नांदेड: नांदेड़-वाघाळा महानगरपालिका चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा सांसद अशोकराव चव्हाण ने कांग्रेस पर जोरदार राजनीतिक हमला बोला और आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी संविधान बदलने का झूठा प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रचार जनता को गुमराह करने वाला है और अब कांग्रेस को “धोखा देने” के इस रवैये पर उन्हें सीख देने का समय आ गया है।

चव्हाण ने चौफाळा भाग में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही और कहा कि भाजपा संविधान को मानने वाली पार्टी है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में

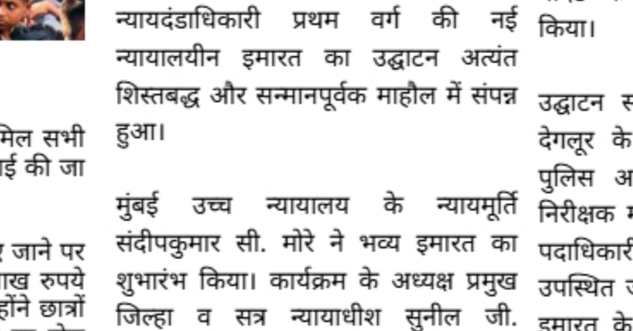

पहले प्रवेश के समय संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त कर चुके हैं और भाजपा सरकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों के अनुरूप ही काम कर रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास अब कोई ठोस एजेंडा नहीं बचा है और वे आलोचना के लिए भी अपने असली मुद्दों को छोड़कर संविधान जैसे गंभीर विषय का अपप्रचार कर रहे हैं। चव्हाण ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस का राजनीतिक प्रभाव घट रहा है और पार्टी अब कमजोर स्थिति में है।

अपने भाषण में चव्हाण ने नांदेड के विकास पर भी जोर दिया, कहा कि भाजपा का विकास एजेंडा स्पष्ट है और शहर के लिए योजनाएं तैयार हैं। उन्होंने बारा बलुतेदार समुदाय सहित स्थानीय बचत समूहों को समर्थन देने तथा पुराने नांदेड में लंबित विकास कार्यों को पूरा करने का वादा भी किया।

चव्हाण ने मतदाताओं से भाजपा उम्मीदवारों को मजबूत समर्थन देने का आग्रह किया, ताकि प्रचार में दिए गए वादों को पूरा किया जा सके और संविधान की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

इस प्रकार स्थानीय चुनाव के दौरान संविधान के मुद्दे को मुख्य जोर देकर भाजपा ने कांग्रेस पर राजनीतिक आक्रमण तेज कर दिया है, जिससे चुनावी लड़ाई और अधिक गर्म होती दिख रही है।

हिंगोली: बीपीएल राशन पाने के लिए रिश्वत लेते लिपिक गिरफ्तार

हिंगोली: बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) तथा प्राधान्य परिवार योजनाओं के तहत सस्ती राशन सुविधा दिलाने के नाम पर रिश्वत लेते हिंगोली तहसील कार्यालय के एक लिपिक को लाचलुचपत निरोधक विभाग (एसीबी) ने रंगेहाथ पकड़ा। आरोपी चक्रधर पंडितराव कदम (39) बी.पी.एल. लाभार्थियों को राशन देने के लिए 3,000 रुपये रिश्वत ले रहा था, तभी उसे साजिश के तहत जाल बिछाकर दस्तयाब किया गया।

घटना 8 जनवरी की दोपहर को कळमनुरी तहसील कार्यालय में हुई, जहां एसीबी की टीम ने शिकायत मिलने के बाद कदम के खिलाफ सप्लाई विभाग में सठियाना लगाया। आरोप है कि उन्होंने लाभार्थी परिवार का नाम योजनाओं में शामिल कराने और राशन का लाभ पाने के लिए कुल 8,000 रुपये की मांग की थी, लेकिन जांच में सामने आया कि दो फाइलों के लिए उन्होंने पहले से ही 3,000 रुपये रिश्वत स्वीकार करने पर सहमति दी थी।

एसीबी ने रिश्वत की राशि को दस्तावेज और गवाहों की मौजूदगी में टेबल के दराज़ में डालते ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से कार्यालय की चाबी, पहचान पत्र, मोबाइल फोन व अन्य सामान जब्त किए गए हैं। आवश्यक होने पर मोबाइल को भी जांच के लिए रख लिया गया है।

पुलिस ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है और आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कारवाई जारी है। जांच इंस्पेक्टर राजेश मलपिलू कर रहे हैं, और यह कार्रवाई एसीबी नांदेड के नेतृत्व में की गई है।

यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त प्रशासनिक रुख को दर्शाती है और दर्शाती है कि सरकारी योजना के लाभों के दुरुपयोग पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

स्वाधिकारी नंदिग्राम टाईम्स (नांदेड़) के मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक शेख जहूर शेख अहेमद द्वारा सहारा डिजाइनिंग एंड ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, वाजेगांव, ता. व जि. नांदेड़ में मुद्रित तथा दैनिक नंदिग्राम टाईम्स, मुल्लाह मार्केट, खवी बिल्डिंग, नगरेश्वर मंदिर, नांदेड़–431604 (महाराष्ट्र) के कार्यालय से प्रकाशित। RNI-MAHHIN/2016/69743 मोबाइल संपर्क: 9921100075 | Email: ntinfodesk@gmail.com (वाद-विवाद हेतु न्यायक्षेत्र: नांदेड़ न्याय कक्षा में।)